हैं। राजस्थान में भूभाग का बड़ा क्षेत्र इन फसलों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और राजस्थान इन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि राज्य के कई जिलों में उक्त फसलें प्रमुख फसलों के रूप में बोई जाती हैं।

महोदय, परन्तु क्योंकि ये फसलें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत नही आती, इसलिए राजस्थान में इन फसलों की खेती करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का लाभ नही उठा पाते। फलस्वरूप, किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को ही बेचकर संतोष करना पड़ता है और जिसमें कई बार उन्हें अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल नही मिल पाता। अत: मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राजस्थान के किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का दायरा बढ़ाया जाए और इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में लाया जाए, जिससे राजस्थान के किसान भी अपनी इन फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

श्री लाल सिंह वड़ोडिया (गुजरात): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा सदन में उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा सदन में उठाए गए विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Shri Md. Nadimul Haque. Please be brief because I have to cover others also.

Demand to take steps to increase youth participation in higher education

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, higher education plays a key role in economic growth and development of a country. The private as well as social returns from investment in higher education are generally significant for countries with low per capita income.

The latest All India Survey of Higher Education found that less than 0.5 per cent students are enrolled in PhD programmes in the country. PhD enrolment in Central Universities is less than 5 per cent of total PhD enrolment.

Indian students are increasingly choosing to pursue postgraduate studies abroad However, the share of foreign students pursuing PhD programmes in India is less than 3 per cent of the total foreign enrolment.

Public expenditure on education and research and development has to increase in India. Although India's investment in R&D has increased over the years, public expenditure as a fraction of GDP has been constant at 0.6 per cent to 0.7 per cent for the last two decades. This is in contrast to countries like China and US who spend more than 2 per cent as a fraction of their GDP on the same. Similarly, public expenditure on education must reach at least 6 per cent and possibly 10 per cent of the GDP. Along with increased spending, we must incentivize teaching as a profession to attract the brightest minds.

Providing access to higher education is necessary to break systemic social barriers. Its importance today cannot be stressed further for the most marginalised sections of Indian society. I urge the Government to take steps in order to make postgraduate studies and research more attractive for both domestic and foreign students.

MR. CHAIRMAN: Dr. Ashok Bajpai, not present. Shri Rajmani Patel.

Demand to extend Railway network in Madhya Pradesh

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, किसी भी क्षेत्र में प्रगति और विकास के लिए रेलवे यातायात का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश में कई जिले काफी पिछड़े हुए हैं, जहां रेलवे यातायात की सुविधा बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि बनारस से हनूमना मऊगंज मनगवां होते हुए रीवा तक तथा इलाहाबाद से चाक त्योथर कटरा लालगाँव बैकुण्ठपुर सेमरिया होते हुए सतना तक नवीन रेल पथ का निर्माण किया जाए।

इसी तरह रीवा से सतना, पन्ना, छतरपुर, सागर होते हुए भोपाल तक नवीन रेल पथ का निर्माण किया जाना आवश्यक है, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

साथ ही डभौरा में ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए तथा ऊर्जा नगरी अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन चचाई मेडियारास में बना है। मेडियारास की आबादी 3,000 है, चचाई की 10,000 है, चकेठी की 3,000 है, परसकर की 5,000 है, सभी की मिलाकर 50,000 की आबादी है, जिन्हें अक्सर रेल सफर करना पड़ता है। रेलवे सुविधा होते हुए स्टेशन नही होने से 8 किलो मीटर दूर जाने में जनता को विशेष कठिनाई होती है। अत: मेडियारास को स्टेशन बनाया जाए, ताकि यात्रियों को आसानी से रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

मैं भारत सरकार तथा रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्रवाई के आदेश देने की कृपा करें।